



भारत में आधार को लेकर चर्चाएँ

प्रलिस के लयि:

महातमा गांधी राषटरीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण (UIDAI), वकिंदरीकृत आईडी (DID)

मेन्स के लयि:

नागरकिों की सुरक्षा और गोपनीयता पर डजिटल इंडया का प्रभाव

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यो?

भारत के व्यापक डजिटल बुनयादी ढाँचे का विकास कार्य नरितर जारी है, कति हाल ही में मूडीज़ की "वकिंदरीकृत वतित और डजिटल परसिंपतता" शीरषक से प्रकाशति रपिरट में रेखांकति कया गया है कविश्व का सबसे बड़ा डजिटल पहचान कार्यक्रम उपयोगकर्त्ताओं को नयिमति सेवाएँ प्रदान करने में वकिल रहा है।

- यह रपिरट बायोमेट्रकि तकनीक की नरिभरता को लेकर चर्चाएँ व्यक्त करती है, साथ ही गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी संभावति जोखमिों के बारे में चेतावनी भी देती है।

रपिरट के प्रमुख बट्टि:

- गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चर्चाएँ:
 - इस एजेंसी के अनुसार 'आधार' (AADHAR) और 'वर्ल्डलाइन (एक नना करपिटो-आधारति डजिटल पहचान टोकन) वशि्व की दो ऐसी डजिटल पहचान प्रणाली हैं जो अपने पैमाने और नवाचार के कारण सबसे अलग हैं।
 - हालाँकि उनकी "गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में जाँच व्यवस्था दुरुस्त है", कति आधार से संवेदनशील जानकारी वशिषिट संस्थाओं के पास केंद्रति होने से डेटा उल्लंघनों का खतरा भी बना रहता है।
- बायोमेट्रकि प्रमाणीकरण संबंधी चर्चाएँ:
 - रेटगि एजेंसी ने अपनी रपिरट में महातमा गांधी राषटरीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियिम (मनरेगा) आदजैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थयिों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लयि सरकार द्वारा आधार प्रणाली को अपनाने को लेकर टपिपणी की, रेटगि एजेंसी के अनुसार आधार प्रणाली इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में काफी सीमा तक बाधा बन रही है।
 - आधार बायोमेट्रकि प्रणाली में प्रमाणीकरण और बायोमेट्रकि वशि्वसनीयता संबंधी कई चर्चाएँ शामिल हैं।
 - आधार प्रणाली फगिरप्रटि अथवा आँख के आईरसि स्कैन तथा वन-टाइम पासकोड (OTP) जैसे वकिल्पों के माध्यम से सत्यापन करके सार्वजनकि और नजिी सेवाओं तक पहुँच की सुवधि प्रदान करती है।
- सेवाओं की बाधारहति उपलब्धता संबंधी चर्चाएँ:
 - भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण (UIDAI) आधार को प्रबंधति करता है, जसिका लक्ष्य वंचति समूहों को एकीकृत करना और कल्याणकारी लाभों की पहुँच का वसितार करना है।
 - वशिषि रूप से गरम, आरुद्र जलवायु में रहने और शारीरकि रूप से काम करने वाले शरमकिों/लोगों के बीचआधार सेवाओं की बाधारहति उपलब्धता एवं बायोमेट्रकि प्रौद्योगकियिों की वशि्वसनीयता कई बार सवालों के घेरे में आती है।
- डेटा के केंद्रीकरण से संबंधति मुद्दे:
 - मूडीज़ ने डजिटल वॉलेट जैसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगकिकी आधारति वकिंदरीकृत आईडी (DID) प्रणाली का प्रस्ताव रखा है, जो उपयोगकर्त्ताओं को उनके नजिी डेटा पर अधिक नयितरण प्रदान करते हैं और संभावति रूप से ऑनलाइन धोखाधट्टी को कम करता है।

मूडीज़ की रपिरट पर सरकार की प्रतिकरिया:

■ आधार को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा मान्यता:

- सरकार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने आधार प्रणाली की सराहना की है तथा विभिन्न देशों ने भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण जैसी ही डिजिटल आईडी प्रणाली तैयार करने पर चर्चा भी की है।

■ मनरेगा जैसी योजनाओं की सुवधा:

- सरकार ने बताया कि रिपोर्ट के जारीकर्ताओं को शायद यह जानकारी नहीं है कि मनरेगा डेटाबेस में आधार की जानकारी अंकित करने के लिये उनको बायोमेट्रिक्स की सहायता से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।

■ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ:

- सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान सीधे उनके खाते में पैसा जमा करके किया जाता है और इसके लिये उन्हें अपने बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ:

- एक केंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथवा सरकारी मतदाता सूची जैसी इकाइयाँ उपयोगकर्ता की पहचान संबंधी विश्वसनीयता और ऑनलाइन संसाधनों तक उनकी पहुँच को न्यंत्रित एवं प्रबंधित करती है।
 - प्रबंधन इकाइयाँ आंतरिक अथवा थर्ड-पार्टी प्रोफाइलिंग उद्देश्यों के लिये उपयोगकर्ता के पहचान डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकती है।
- हालाँकि DID का अंगीकरण (जिसमें व्यक्तिगत डेटा उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में सहेजा जाता है) और पहचान सत्यापन कार्य एक एकल, केंद्रीकृत संस्थान के माध्यम से नहीं बल्कि ब्लॉकचेन जैसे विकेंद्रीकृत डिजिटल बहीखाता के माध्यम से होता है।
 - यह गोपनीयता में वृद्धि करता है और मध्यस्थों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी की मात्रा को कम करता है।
 - इसे किसी सरकार, व्यवसाय, न्योक्ता या अन्य इकाई के बजाय उपयोगकर्ता के पोर्टेबल और पुनः प्रयोज्य डिजिटल वॉलेट में संगृहीत तथा प्रबंधित किया जा सकता है।

विकेंद्रीकृत पहचान प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ:

- डिजिटल आईडी चाहे वे केंद्रीकृत हों या नहीं, हानिकारक सामाजिक प्रभाव डाल सकती हैं क्योंकि वे समूहों के बीच राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती हैं, खासकर तब, जब वे एकाधिकार प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया व्यवसायों द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- इन संगठनों के भीतर न्यंत्रण के संकेंद्रण के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत पहचान पर प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, साथ ही विभिन्न धारणाएँ तथा ऑनलाइन गतिविधियाँ भी प्रभावित हो सकती हैं।
- सामूहिक पहचान एवं राजनीतिक संबद्धताओं के और अधिक ध्रुवीकरण से एकीकृत तथा विविधतापूर्ण डिजिटल तंत्र के निर्माण का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।

आधार (Aadhaar):

- आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी की गई 12 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
 - आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिये वशिष्ट होती है और इसकी वैधता जीवन भर तक है।
 - आधार संख्या नविसियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है।
 - यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है।
 - वर्तमान दस्तावेजों के बावजूद, प्रत्येक नागरिक इस स्वैच्छिक सेवा का उपयोग कर सकता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):

- उद्देश्य:
 - इसे लाभार्थियों तक सूचना और धन के सरल/तेज़ प्रवाह तथा वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने में सहायता करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- क्रियान्वयन:
 - यह भारत सरकार द्वारा सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार के लिये 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया एक मिशन है।
- केंद्रीय योजना स्कीम नगिरानी प्रणाली (CPSMS), लेखा महानियंत्रक कार्यालय की [सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली](#) (PFMS) का

पूर्व संस्करण, को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूटिंग के लिये सामान्य मंच के रूप में कार्य करने के लिये चुना गया था।

■ **DBT के अवयव:**

- DBT योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिक घटकों में **लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली**, **भारतीय रज़िर्व बैंक**, **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम** (National Payments Corporation of India- NPCI), **सार्वजनिक एवं नज़ी क़्षेत्र के बैंकों**, **क़्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** तथा **सहकारी बैंक** (बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की नपिटान प्रणाली व NPCI का आधार भुगतान माध्यम) आदि के साथ **एकीकृत** एक मज़बूत भुगतान और समाधान मंच शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक़्षा, वत्ति वरष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. “ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी” के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2020)

1. यह एक सार्वजनिक बहीखाता है जसिका नरीक़्षण हर कोई कर सकता है, लेकनि जसि कोई एकल उपयोगकर्त्ता नयित्त्रति नहीं करता है।
2. ब्लॉकचेन की संरचना और डज़ाइन ऐसा है क इंसमें मौजूद सारा डेटा क़्रप्टोक़रेंसी के बारे में ही होता है।
3. ब्लॉकचेन की बुनयिादी सुवधिाओं पर नरिभर एप्लीक़ेशन बनिा कसिी की अनुमत्ता के वकिसति कयि जा सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (d)